

राजघराने में आपसी समझौते के बाद जयमहल पैलेस देवराज और लालित्य कुमारी को मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के बाद हुआ महत्वपूर्ण समझौता



जयपुर राजघराने में सम्पत्ति का विवाद और जयमहल पैलेस होटल के स्वामित्व का विवाद आपसी समझौते से 15 दिसम्बर को सलट गया है। समझौते के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और मध्यस्थ व जस्टिस कुरियन जोसफ (बैठे हुए बाँये से दूसरे) उनके पास बैठे हैं जयसिंह। खड़े हुए बाएँ से दूसरे अजय सिंह, वकील संजीव सेन, देवराज सिंह, विजित सिंह, वकील अभिषेक राव, और ठाकुर हरीसिंह।

-प्रकाश भण्डारी-
जयपुर, 17 दिसम्बर। राजघराने के सदस्यों बीच लम्बे समय से चला आ रहा शहर के नामकीन पांच सितारा हैरिटेज होटल जयमहल पैलेस विवाद

आपसी समझौते के बाद निपट गया है। जयमहल पैलेस, जिस पर स्वर्गीय महाराज पृथ्वीराज और उनके पुत्र विजित सिंह का आधिपत्य था, लेकिन अब इस समझौते के बाद इस बेहतरीन

पैलेस होटल कर मालिकाना हक राजमाता गायत्री देवी के पौत्र देवराज सिंह और पौत्री लालित्य कुमारी के पास चला जाएगा। भविष्य में इस सम्पत्ति का संचालन और नियंत्रण अब स्वर्गीय

सवाई मानसिंह और राजमाता गायत्री देवी के पुत्र स्वर्गीय जगतसिंह के पुत्र और पुत्री करेंगे। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय जगतसिंह सवाई मानसिंह और

राजमाता गायत्री देवी की एकमात्र संतान थी। सवाई मानसिंह ने पचास वर्ष पूर्व जयमहल पैलेस का एकमात्र स्वामी जगतसिंह को बनाया था। यह महल उन्हें गिफ्ट किया था। जगतसिंह का विवाह थाईलैण्ड के राजपरिवार की प्रियनन्दना रंगसोत के साथ हुआ था जिससे दो संतानें देवराज सिंह और लालित्य कुमारी हुईं। लेकिन जगतसिंह और रानी प्रियनन्दना के बीच अनबन के चलते तलाक हो गया था। विवाह के दौरान जगतसिंह प्रियनन्दना और उनके दोनों बच्चे लन्दन में ही रहते थे। लेकिन तलाक के बाद रानी प्रियनन्दना दोनों बच्चों को लेकर अपने देश थाईलैण्ड लौट गईं और वह अपने दोनों बच्चों के साथ बैंकॉक में रह रही थी।



लालित्य कुमारी और देवराज सिंह



जयसिंह (दाएं) और भतीजे

तलाक के बाद रानी प्रियनन्दना ने अपने पूर्व विवाह से उत्पन्न संतानों को जयपुर के राजपरिवार में उनके सम्पत्ति के अधिकार के लिए और उन्हें उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में स्वर्गीय महाराजा सवाई भवानी सिंह ने उनका पूरा सहयोग दिया। भवानी सिंह के ठोस सहयोग के कारण देवराज सिंह और लालित्य कुमारी ने 15 वर्षों तक विभिन्न स्तर पर कानूनी लड़ाई (शेष पृष्ठ 7 पर)

अमेठी

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी को केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों हारने के बाद वहां के दौरे पर सिर्फ एक ही बार गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभियान की शनिवार से शुरुआत की और इसके लिए अमेठी का ही चयन किया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को घोषणा की

■ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का यू.पी. का चुनाव अभियान शनिवार से "जन जागरण पद यात्रा" से शुरू करेंगे।

कि राहुल शनिवार सुबह 11 बजे अमेठी जिले के जगदीशपुर से अपने (शेष पृष्ठ 7 पर)

अमरिन्दर सिंह ने गजेन्द्र सिंह शेखावत के समक्ष चुनावी समझौते पर हस्ताक्षर किये

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह (79), जिन्हें सतारुद कांग्रेस से अभी हाल ही में निष्काशित कर दिया गया था, ने शुक्रवार को अपनी नवगठित पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का चुनावी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से करने की घोषणा कर दी। उन्होंने अगले वर्ष के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनावों गठबंधन की सुनिश्चित जीत का दावा किया।

पंजाब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (58) के साथ चल रही अधिकारों की लड़ाई में कांग्रेस नेतृत्व द्वारा अपमानित कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ दी थी तथा उसके बाद

अब उन्होंने अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना ली है। केन्द्रीय जल-शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, जो पंजाब के पार्टी प्रभारी के साथ सात चरणों के अंतिम एवं निर्णायक चरण की वार्ता के बाद, कैप्टन ने यहां उक्त घोषणा कर दी।

■ अमरिन्दर सिंह ने इस मौके पर दावा किया कि, यह चुनावी गठबंधन आगामी चुनाव में जीत हासिल करेगा।

■ पंजाब के पूर्व मु. मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को कांग्रेस ने पार्टी से निष्काशित किया था।

इस महीने की शुरुआत में, अमरिन्दर सिंह ने शिरोमणि अकाला दल (संयुक्त) के सुखदेव सिंह ढींढसा के नेतृत्व वाले गुट के साथ गठबंधन की संवैधानिक घोषणा भी की थी। ढींढसा 2010 से राज्यसभा के सदस्य हैं। फिर उन्होंने कहा था कि वे ढींढसा, भाजपा तथा अपनी पार्टी से कहेंगे कि वे जितना नेताओं का चयन करें तथा उन्हें अपना समर्थन एवं सहयोग प्रदान करें।

भाजपा ने मैट्रो रेल-प्रोजैक्ट्स की बौछार लगा दी यू.पी.में

कानपुर में आई.आई.टी. से मोतीझील, आगरा मैट्रो का 6 किलोमीटर रन, गोरखपुर में 15.4 किलोमीटर का मैट्रो रेल का टुकड़ा, बनारस में रेल मंत्रालय का रोप-वे प्रोजैक्ट

- श्रीनंद झा -

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी से मोतीझील की 9 किमी दूरी को जोड़ने वाले कानपुर मैट्रो के पहले चरण पर 28 दिसम्बर को वाणिज्यिक संचालन का उद्घाटन करेंगे। इसके 6 किमी. लम्बे प्रमुख भाग को संचालित करने के लिए, जिसमें तीन एलिवेटेड और तीन अण्डरग्राउण्ड स्टेशन हैं, आगरा मैट्रो के अधिकारी कठिन परिश्रम कर रहे हैं। भारत के सार्वजनिक निवेश बोर्ड से अनापत्ति मिलने के बाद गोरखपुर में 15.4 किमी का मैट्रो लाइट रेल प्रोजैक्ट निर्मित करने के लिए 22 सौ करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट को मंत्रिमण्डल की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है।

मेरठ में भी अगले वर्ष दो मैट्रो लाइन्स को संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 424 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक रोप वे शुरू करने के प्रस्ताव पर भी

काम शुरू कर दिया गया है। आंतरिक सर्वे की इन रिपोर्टों के बीच कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में भाजपा की संभावनाएं उज्ज्वल नहीं हैं, पार्टी नेतृत्व ने हाल ही के दिनों में

■ यू.पी. में खस्ता हालात से धिरी भाजपा, कुछ धार्मिक और कुछ विकास के नारे को आधार बना रही है वोट बटोरने के लिये।

■ एक चौकाने वाला तथ्य है कि, 2012-17 तक अखिलेश के शासन में जी.डी.पी. ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा थी, और अब योगी आदित्यनाथ शासन में ग्रोथ रेट आधी रह गयी है।

अपने चुनावी अभियानों में पूरा जोर लगा दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व के साथ एक हिन्दू धार्मिक अपील को विकास के जोश के साथ जोड़ दिया गया है। जैसी कि "राष्ट्रदूत" में पहले

खबर दी जा चुकी है, केन्द्र सरकार भी उत्तर प्रदेश में कई रेल प्रोजैक्ट्स की घोषणा करेगी। देखा यह जा रहा है कि क्या अंतिम क्षणों में दिखाए गए विकास के जोश से भाजपा को मदद मिलेगी और योगी आदित्यनाथ सरकार सत्ता विरोधी मनोभावों पर पार पा सकेगी।

एक तथ्य, जिस पर ज्यादा बात नहीं हो रही है, यह है कि अखिलेश यादव के पूर्व के कार्यकाल (2012-17) के दौरान राज्य की जी.डी.पी. विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा थी और योगी आदित्यनाथ के अधीन भाजपा शासन में रही जी.डी.पी. विकास दर की तुलना में लगभग दोगुनी थी। कोविड कुप्रबन्धन से लेकर बढ़ती कीमतें और बेरोजगारी से लेकर बिगड़ती कानून व्यवस्था योगी सरकार की मूलभूत कमियां रही हैं। वर्ष 2017 की स्थिति के विपरीत जातिगत समीकरण भी भाजपा के पक्ष में प्रतीत नहीं होते हैं। पार्टी की उम्मीदें अपनी धुवीकरण की रणनीति और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत आकर्षण पर ही पूर्णतया निर्भर हैं। अतः उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनावी संघर्ष मोदी बनाम अखिलेश में तब्दील होता नजर आ रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को एक साइड हीरो के तौर पर देखा जा रहा है।

जब दिल में हो जज़्बात, तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत

Scan to watch our latest film

Toll-free No.: 1800 31 31 31 | wondercement.com